

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

चर्चा में क्यों?

कोवडि-19 महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में हजारों बच्चों को अपने माता-पिता को खोने का वनिाशकारी दुख का सामना करना पड़ा।

- राज्य सरकार ने **मध्य प्रदेश के कोवडि अनाथ बच्चों** के लिये **वित्तीय सहायता** और **मुफ्त शिक्षा** का वादा किया था, लेकिन इनमें से कई प्रतबिद्धताएँ पूरी नहीं हो पाईं, जिससे बच्चे संकट में हैं।

प्रमुख बडि

- मई 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान ने घोषणा की थी कि जिनि बच्चों ने **कोवडि-19** के कारण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उन्हें **5,000 रुपए प्रतमाह** और **मुफ्त शिक्षा** मल्लिगी।
- इस पहल का उद्देश्य प्रभावति परिवारों को कुछ राहत प्रदान करना तथा यह सुनिश्चति करना था कि बच्चे बनिा किसी वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
 - इन वादों के बावजूद, वभिनिन् लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय से वित्तीय सहायता नहीं मल्लि है।
- सरकार ने इन बच्चों के लिये दो योजनाएँ शुरू की थीं: **स्पॉन्सरशिप योजना** और **मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना**। इन योजनाओं के तहत, प्रत्येक बच्चे को **5,000 रुपये प्रतमाह** दिये जाने का प्रावधान था।
 - हालाँकि, धनराशा का वितरण असंगत रहा है, और कई बच्चों को जनवरी 2023 से कोई धनराशा नहीं मल्लि है।
- बच्चों को उनके स्वास्थय देखभाल खर्च को पूरा करने के लिये **आयुषमान भारत कार्ड** देने का भी वादा किया गया।
 - हालाँकि, इनमें से कई कार्ड सक्रिय नहीं किये गए हैं, जिससे बच्चों को वादे के अनुसार चकितिसा सहायता नहीं मल्लि पाई है।